



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 256]  
No. 256]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 1982/ज्येष्ठ 31, 1904  
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 1982/JYAISTHA 31, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय  
आर्थिक कार्य विभाग  
अधिलेखना

नई दिल्ली, 21 जून, 1982

का० आ० संख्या 434(अ) :— राष्ट्रपति द्वारा दिया गया निम्न लिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 और वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1951 (1951 का 33) के उपबन्धों के अनुसरण में राष्ट्रपति ने प्रसन्नतापूर्वक श्री यशवन्तराव चव्हाण संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक वित्त आयोग स्थापित किया है उसके अन्य चार सदस्य ये होंगे :—

1. न्यायमूर्ति श्री सच्चिदाचारी मुखर्जी  
न्यायाधीश कलकत्ता उच्च न्यायालय ।
2. डा० सी० एच० हनुमन्तराव  
सदस्य योजना आयोग ।
3. श्री जी० सी० बवेजा  
सचिव वित्त मंत्रालय ।
4. श्री ए० भार० शिराली  
भारत के उप निबंधक-महालेखापरीक्षक ।

2. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य जिन जिन तारीख को अपने कार्यभार ग्रहण कर लेंगे उस तारीख से लेकर 31 अक्टूबर, 1982 तक अपना-अपना पद धारण करेंगे ।

3. अध्यक्ष आयोग को अंशकालिक सेवा प्रदान करेंगे । न्यायमूर्ति श्री सच्चिदाचारी मुखर्जी और डा० सी० एच० हनुमन्तराव सदस्य के रूप में अंशकालिक सेवा प्रदान करेंगे । श्री जी० सी० बवेजा 30 जून, 1982 तक अंशकालिक और उसके बाद पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे । श्री ए० भार० शिराली पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे ।

4. आयोग निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिफारिशें करेगा :—

(क) संघ और राज्यों के बीच उन करों से प्राप्त होने वाली निवल राशियों का बटवारा जो संविधान के भाग XII के अध्याय 1 के अंतर्गत उनके बीच बांटे जाया करते हैं या बांटे जा सकते हैं, और इस प्रकार प्राप्त हुई राशियों में प्रत्येक राज्य के हिस्से का निर्धारण ;

(ख) वे सिद्धांत जिनके आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को उनके राजस्व के सहायक अनुदान दिए जाने चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 275 के खण्ड (1) में निविष्ट प्रयोजनों से उन राज्यों को दी जाने वाली धनराशि जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत उनके राजस्व संबंधी सहायक अनुदानों के रूप में सहायता की जरूरत है ।

5. अपनी सिफारिशें करते हुए आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखेगा :—

- (i) केन्द्रीय सरकार के साधन और सिविल प्रशासन, रक्षा और सीमा सुरक्षा, ऋण शोधन तथा अन्य वचनबद्ध व्यय प्रयत्न देनवारियों पर होने वाले व्यय के कारण उन पर मांगें ;
- (ii) राज्यों की आयोजनाओं के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के निर्धारण और वितरण के सम्बन्ध में मौजूबा पद्धति ;
- (iii) उन राज्यों में 1983-84 के वित्तीय वर्ष के अन्त में कराधान के संभाव्य स्तर पर आधारित उनके 1988-89 के वित्तीय वर्ष के अन्त में समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए राजस्व साधन और आयोजना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाने के वास्ते निर्धारित लक्ष्य ;
- (iv) प्रशासन व्यय और अन्य आयोजना-भिन्न वचनबद्धताओं प्रयत्न देनवारियों को पूरा करने के लिए तथापि राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए उन राज्यों के राजस्व खाते की आवश्यकताएं । इन आवश्यकताओं का निर्धारण करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :—
  - (क) आयोग द्वारा उचित रूप से निर्धारित एक विशिष्ट तारीख की स्थिति के अनुसार और समुचित वस्तुपरक कसौटियों के संदर्भ में, न कि वास्तव में की गई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतन-भत्तों और सेवास्त प्रमुविधाओं के लिए की गई व्यवस्था ; और
  - (ख) उनके ऋण के व्याज स्थानीय निकायों और सहायता प्राप्त संस्थाओं के धन के अन्तरण से संबंधित वचन-बद्धताएं ;
- (v) पूंजीगत परिसम्पत्तियों का समुचित अनुरक्षण और रख-रखाव तथा 1983-84 के अन्त तक पूरी होने वाली आयोजनागत योजनाओं का अनुरक्षण, ऐसे प्रतिमान, यदि कोई हों, जिनके आधार पर विभिन्न श्रेणियों की पूंजीगत परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण के लिए निर्दिष्ट धन राशियां स्वीकार की जाती हैं और वह तरीका जिसके द्वारा इस अनुरक्षण व्यय पर निगरानी रखी जा सके, आयोग द्वारा बताया जाएगा ;
- (vi) विकास-भिन्न क्षेत्रों तथा सेवाओं के मामले में राज्यों, विशेषकर सामान्य प्रशासन की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के स्तरों को अपेक्षाकृत अधिक उन्नत राज्यों में विद्यमान प्रथवा सम्भाव्य स्तरों तक ऊंचा उठाने के लिए राज्यों की आवश्यकताएं ; आयोग इस व्यय पर निगरानी रख सकने का तरीका भी बताएगा ;
- (vii) कार्यकुशलता को बनाए रखते हुए व्यय में किराया और राज्य संबंधी बेहतर प्रबंध की गुंजाइश ; और
- (viii) सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं परिवहन उपक्रमों औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उद्यमों तथा ऐसे ही अन्य कार्यों में लगाई गई पूंजी से उचित आमदनी मुनिश्चित करने की जरूरत ।

6. आयोग चाहे तो

- (क) कृषि भूमि से भिन्न सम्पत्ति सम्बन्धी सम्पदा शुल्क में किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त निवल राशियों,

(ख) निम्नलिखित वस्तुओं, अर्थात्

- (i) सूती कपड़ा
- (ii) ऊनी कपड़ा
- (iii) रेत या तकली रेशम का कपड़ा

(iv) चीनी, और

(v) तम्बाकू जिसमें निर्मित तम्बाकू भी शामिल है,

में से प्रत्येक पर बिक्री करों के स्थान पर जो पहले राज्यों द्वारा लगाए जाने थे अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत लगाए जा सकने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के रूप में किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त निवल राशियों के

राज्यों के बीच बंटवारे के सिद्धान्तों में परिवर्तन करने का सुझाव दे सकता है ; किन्तु प्रत्येक राज्य को मिलने वाला हिस्सा उस राज्य में 1956-57 के वित्तीय वर्ष में बिक्री कर लगाए जाने से बसूल हुए राजस्व से कम नहीं होगा ।

इसके अलावा, आयोग

(ग) निरस्त रेल यात्री भाड़ा कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत लगने वाले कर के स्थान पर राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान, और

(घ) कृषिक सम्पत्ति पर धन-कर के कारण राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के राज्यों के बीच बंटवारे के सिद्धान्तों में परिवर्तन करने का सुझाव दे सकता है ।

7. उपर्युक्त विभिन्न मामलों में अपनी सिफारिशें करने समय, आयोग उन सभी मामलों में 1971 की जनसंख्या के आंकड़े अपनाएगा जिनमें करों और शुल्कों तथा सहायक अनुदानों के हिस्से का निर्धारण करने के लिए जनसंख्या को एक आधार माना जाता है ।

8. आयोग उन करों और शुल्कों से, जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 269 में किया गया है लेकिन जो इस समय लगे हुए नहीं हैं, राजस्व जुटाने और संविधान के अनुच्छेद 268 में उल्लिखित शुल्कों से राजस्व में वृद्धि करने की गुंजाइश की जांच कर सकता है ।

9. आयोग 1988-89 के समाप्त होने वाले पांच वर्षों के लिए एक समान और तुलनात्मक आधार पर राज्यों के आयोजना-भिन्न पूंजीगत अन्तर का निर्धारण कर सकता है । ऐसे निर्धारण को ध्यान में रखते हुए, आयोग उन केन्द्रीय ऋणों के विशेष संदर्भ में, जो राज्यों को दिए गए हैं और जिनके 1983-84 के अन्त में बकाया रहने की संभावना है राज्यों की ऋण सम्बन्धी स्थिति की सामान्य समीक्षा कर सकता है और अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के समग्र आयोजना-भिन्न अन्तर उनकी सापेक्षिक स्थिति और उन प्रयोजनों जिनके लिए ऋणों का उपयोग किया गया है और केन्द्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, आयोजना-भिन्न पूंजीगत अन्तर के बारे में कार्रवाई करने के लिए समुचित उपाय कर सकता है ।

10. आयोग दैवी विपत्तियों से प्रभावित राज्यों द्वारा किए जाने वाले राहत व्यय के वित्त पोषण से सम्बन्धित नीति और प्रबन्धों की समीक्षा कर सकता है और अन्य बातों के साथ-साथ व्यय से बचने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान प्रबंधों में परिवर्तन करने के बारे में ऐसे सुझाव दे सकता है जिन्हें वह समुचित समझे ।

11. आयोग उपर्युक्त प्रत्येक विषय पर और पहली अप्रैल, 1984 से शुरू होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 1983 तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और वह रिपोर्ट में निकाले गए अपने निष्कर्षों का निर्देश करेगा तथा वह राज्यों के आय और व्यय के पूर्वानुमानों में कोई परिवर्तन करेगा तो उनके सम्बन्ध में अपनाए गए राज्य-वार मानदण्डों का उल्लेख करेगा ।

एन० संजीव रेड्डी  
राष्ट्रपति

दिनांक 20 जून, 1982

[सं० 10(1)-बी (एस)/82]

रा० ना० मलहोत्रा

सचिव (आर्थिक कार्य)

**MINISTRY OF FINANCE**  
(Department of Economic Affairs)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st June, 1982

**S.O. 434 (E) :—**The following Order made by the President is published for general information:—

**ORDER**

In pursuance of the provisions of article 280 of the Constitution of India and of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to constitute a Finance Commission consisting of Shri Y.B. Chavan, Member of Parliament as the Chairman and the following four other Members namely:—

1. Shri Justice Sabya Sachi Mukherjee, Judge, Calcutta High Court.
2. Dr. C.H. Hanumantha Rao, Member, Planning Commission.
3. Shri G.C. Baveja, Secretary, Ministry of Finance.
4. Shri A.R. Shirali, Deputy Comptroller & Auditor General of India.

2. The Chairman and other Members of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto the 31st day of October, 1983.

3. The Chairman shall render part-time service to the Commission. Shri Justice Sabya Sachi Mukherjee and Dr. C.H. Hanumantha Rao shall render part-time service as Members of the Commission, Shri G.C. Baveja shall render part-time service upto 30th June, 1982 and full-time service thereafter. Shri A.R. Shirali shall render full-time service.

4. The Commission shall make recommendations as to the following matters:—

- (a) The distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter 1 of Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;
- (b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the proviso to clause (1) of that article.
5. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to:—
  - (i) the resources of the Central Government and the demands thereon on account of the expenditure on civil administration, defence and border security, debt servicing and other committed expenditure or liabilities;
  - (ii) the existing practice in regard to determination and distribution of Central assistance for financing State Plans;
  - (iii) the revenue resources of those States for the five years ending with the financial year 1988-89 on the basis of the levels of taxation likely to be reached at the end of the financial year 1983-84 and the targets set for additional resource mobilisation for the Plan;
  - (iv) the requirements on revenue account of those States to meet the expenditure on administration and other non-Plan commitments or liabilities, keeping however in view national policies and priorities. In assessing

such requirements, the Commission shall take into account:—

- (a) such provision for emoluments and terminal benefits of Government employees, teachers and employees of local bodies as obtaining on a specified date as the Commission deems it proper and with reference to appropriate objective criteria rather than in terms of actual increases that may have been given effect to; and
- (b) commitments in regard to interest charges on their debt, transfer of funds to local bodies and aided institutions;
- (v) adequate maintenance and upkeep of capital assets and maintenance of Plan schemes completed by the end of 1983-84, the norms, if any, on the basis of which specified amounts are allowed for the maintenance of different categories of capital assets and the manner in which such maintenance expenditure could be monitored, being indicated by the Commission;
- (vi) the requirements of States for upgradation of standards in non-developmental sectors and services particularly of States which are backward in general administration with a view to bringing them to the levels obtaining or likely to obtain in the more advanced States, the manner in which such expenditure could be monitored, being also indicated by the Commission;
- (vii) the scope for better fiscal management and economy in expenditure consistent with efficiency; and
- (viii) the need for ensuring reasonable returns on investments in irrigation and power projects, transport undertakings, industrial and commercial enterprises and the like.

6. The Commission may suggest changes, if any, to be made in the principles governing the distribution among the States of:—

- (a) the net proceeds in any financial year of estate duty in respect of property other than agricultural land;
- (b) the net proceeds in any financial year of the additional excise duties leviable under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957, in replacement of the sales tax levied formerly by the State Governments on each of the following commodities; namely:—
  - (i) cotton fabrics;
  - (ii) woollen fabrics;
  - (iii) rayon or artificial silk fabrics;
  - (iv) sugar; and
  - (v) tobacco including manufactured tobacco ;

Provided that the share accruing to each State shall not be less than the revenue realised from the levy of sales tax for the financial year 1956-57 in that State.

- (c) the grant to be made available to the States in lieu of the tax under the repealed Railway Passenger Fares Tax Act, 1957; and
- (d) the grant to be made available to the States on account of wealth tax on agricultural property.

7. In making its recommendations on the various matters aforesaid, the Commission shall adopt the population figures of 1971 in all cases where population is regarded as a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants-in-aid.

8. The Commission may examine the scope for raising revenue from the taxes and duties mentioned in article 269 of the Constitution but not levied at present and the scope for enhancing revenue from the duties mentioned in article 268.

9. The Commission may make an assessment of the non-Plan capital gap of the States on a uniform and comparable basis for the five years ending with 1988-89. In the light of such an assessment, the Commission may undertake a general review of the States' debt position with particular reference to the Central loans advanced to them and likely to be outstanding as at the end of 1983-84 and suggest appropriate measures to deal with the non-Plan capital gap, having regard inter-alia to the overall non-Plan gap of the States, their relative position and the purposes for which the loans have been utilised and the requirements of the Centre.

10. The Commission may review the policy and arrangements in regard to the financing of relief expenditure by the States affected by natural calamities and suggest such modifications

as it considers appropriate, in the existing arrangements, having regard, among other considerations, to the need for avoidance of wasteful expenditure.

11. The Commission shall make its report by the 31st October, 1983 on each of the matters aforesaid and covering a period of five years commencing from the 1st day of April, 1984. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings and make available the State-wise criteria adopted in making modifications, if any, in the States' forecasts of receipts and expenditure.

N. SANJIVA REDDY  
PRESIDENT

Dated the 20th June, 1982.

[No. 10)1-B(S)/82]

R.N. Malhotra, Secretary (Economic Affairs)